भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 80*

07 फरवरी, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष चिकित्सा को बढ़ावा

*80. डॉ. लता वानखेड़े:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा देश में आयुर्वेद, योग और होम्योपैथी जैसी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए कार्यान्वित की जा रही प्रमुख योजनाओं का चिकित्सा पद्धतिवार ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार और आयुष चिकित्सा पद्धतियों के प्रचार-प्रसार के लिए किए जा रहे विशेष प्रयासों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा आयुष क्षेत्र में युवाओं के लिए रोजगार और शैक्षिक अवसर बढ़ाने के लिए किस प्रकार की योजनाएं कार्यान्वित किए जाने का विचार है?

उत्तर

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ग): विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

लोक सभा में 07 फरवरी, 2025 को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 80* के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख) आयुष मंत्रालय देश में आयुर्वेद, योग और होम्योपैथी जैसी आयुष चिकित्सा पदद्धतियों के विकास और संवर्धन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की केंद्रीय प्रायोजित योजना को कार्यान्वित कर रहा है । राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) के माध्यम से राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान सहायता प्रदान की जाती है।

एनएएम अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित गतिविधियों के लिए प्रावधान करता है:

(i) आयुष स्वास्थ्य एवं आरोग्य केन्द्रों (एएचडब्ल्यूसी) का परिचालन अब आयुष्मान आरोग्य मंदिर (आयुष) के नाम से किया जाएगा।
(ii) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (सीएचसी) और जिला अस्पतालों (डीएच) में आयुष सुविधाओं की सह-स्थापना।
(iii) मौजूदा सरकारी आयुष अस्पतालों का उन्नयन।
(iv) मौजूदा सरकारी/पंचायत/सरकारी सहायता प्राप्त आयुष औषधालयों का उन्नयन/मौजूदा आयुष औषधालय के लिए भवन का निर्माण (किराए पर/जीर्ण-शीर्ण आवास)/नए आयुष औषधालय की स्थापना के लिए भवन का निर्माण।
(v) 10/30/50 बिस्तरों वाले एकीकृत आयुष अस्पतालों की स्थापना।
(vi) सरकारी आयुष अस्पतालों, सरकारी औषधालयों और सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थागत आयुष अस्पतालों को आवश्यक दवाओं की आपूर्ति।
(vii) आयुष जन स्वास्थ्य कार्यक्रम।
(viii) उन राज्यों में नए आयुष कॉलेजों की स्थापना, जहां सरकारी क्षेत्र में आयुष शिक्षण संस्थानों की उपलब्धता अपर्याप्त है।
(ix) आयुष स्नातक संस्थानों और आयुष स्नातकोत्तर संस्थानों का अवसंरचनात्मक विकास/पीजी/फार्मेसी/पैरा-मेडिकल पाठ्यक्रमों को शामिल करना।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से एसएएपी के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार, आयुष चिकित्सा पद्धतियों के विकास और संवर्धन के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को 5227.64 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता जारी की गई है। एसएएपी के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को समेकित निधि जारी की जा रही है । हालांकि, प्रणाली-वार कोई निधि जारी नहीं की जा रही है।

इसके अलावा, मंत्रालय आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा सहित आयुष चिकित्सा पद्धतियों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए आयुष में सूचना शिक्षा और संचार (आईईसी) को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय क्षेत्रीय योजना का भी कार्यान्वयन कर रहा है। इसका उद्देश्य देश भर में आबादी के सभी वर्गों तक पहुँचना है। यह योजना राष्ट्रीय/राज्य आरोग्य मेलों, योग फेस्ट/ उत्सवों, आयुर्वेद पर्वों आदि के आयोजन के लिए सहायता प्रदान करती है।

इसके अतिरिक्त, आयुष्मान आरोग्य मंदिर (आयुष) और आयुष अस्पतालों के लिए भारतीय जन स्वास्थ्य मानक (आईपीएचएस) का शुभारंभ 04 मार्च, 2024 को तत्कालीन माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, भारत सरकार द्वारा किया गया है। तदनुसार, इन मानकों को देश में स्वास्थ्य सेवा वितरण की गुणवत्ता में सुधार के लिए अनुपालन हेतु राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के साथ साझा किया गया है।

आयुष मंत्रालय, भारत सरकार और भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) के बीच, इसके बोर्ड, अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाता राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएच) के माध्यम से, राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) के तहत समर्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर (आयुष) और एकीकृत आयुष अस्पतालों के एनएबीएच आयुष प्रवेश स्तर प्रमाणन (एईएलसी) के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(ग) अभी तक, किसी भी नई प्रस्तावित योजना को लागू करने पर विचार नहीं किया जा रहा है। हालांकि, आयुष मंत्रालय के तत्वावधान में, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (एनसीआईएसएम) और राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (एनसीएच) के माध्यम से हर साल नए कॉलेजों को अनुमति दी जा रही है, ताकि रोज़गार बढ़ाने के लिए आयुष शिक्षा पद्धति के तहत अधिक छात्रों को शिक्षित किया जा सके। एनएएम योजना के तहत भी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रो को रोज़गार बढ़ाने के लिए उचित और मानक शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से नए आयुष कॉलेज स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है।

****